

प्रेषक :

अनूप बधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी (जनपद हरिद्वार को छोड़कर),
उत्तराखण्ड।

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग,

देहरादून, दिनांक 07 जून, 2008

विषय : पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान राज्य में सेक्टर कार्यक्रम (स्वजल परियोजना) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 311/XII/08/86(10)/2008 दिनांक 01 अप्रैल, 2008 के अनुसार ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्ति पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायतों में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 माह से अनाधिक अवधि अथवा नई ग्राम पंचायत के गठन तक जो भी पहले हो, प्रशासक नियुक्त करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

पंचायतीराज विभाग से जारी अधिसूचना संख्या 308/86(16)/2005 दिनांक 19 मई, 2005 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में उपभोक्ता आधारित उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समितियों के गठन हेतु उपबंध किया गया है। इन समितियों के माध्यम से ही मांग आधारित पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं ग्राम प्रधान ही उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति का पदेन अध्यक्ष नामित हैं।

शासनादेश संख्या 2425 उन्तीस/04-2(22पे0)/2004 दिनांक 31 मई, 2005 द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में सकल क्षेत्र की समरूप नीति (SWAp) अपनाते हुए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं बाह्य सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के पदेन अध्यक्ष नामित हैं।

प्रदेश में क्रियान्वित किए जा रहे उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना (सेक्टर कार्यक्रम), स्वजलधारा, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्न तथ्य ज्ञातव्य हैं—

- क) परियोजना के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।
- ख) शासन द्वारा चिन्हित संकट ग्रस्त ग्रामों में अविलम्ब पेयजल योजनाओं का निर्माण होना है।
- ग) बी0पी0एल0 परिवारों को निजी शौचालयों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित कर तथा निर्मित शौचालयों हेतु प्रोत्साहन धनराशि का वितरण किया जाता है। ए0पी0एल0 परिवारों से उनके अपने संसाधनों से शौचालय बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

- घ) प्रदेश के समस्त स्कूलों व उचित सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण होना है।
- ङ) प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है।
- च) जल संरक्षण एवं सम्वर्द्धन मिशन के अन्तर्गत चाल-खाल, डिग्गी निर्माण आदि कार्यों को सम्पादित किया जाना।
- छ) परियोजना के अन्तर्गत परियोजना कार्यों हेतु आवंटित धनराशि ग्राम निधि में जमा की जाती है तथा ग्रामनिधि से धनराशि का स्थानान्तरण 15 दिनों के अन्दर उपभोक्ता जल एवं स्वच्छता उप समितियों को किया जाता है।

सैक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त समस्त कार्य समयबद्ध व उपभोक्ता समितियों के माध्यम से किये जाने हैं इन कार्यों को चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक नहीं रोका जा सकता है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यह आवश्यक है कि जिला स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत प्रशासकों द्वारा उपरोक्त अधिसूचना में गठित उप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य सम्पन्न करते हुये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाय। राज्य हित में अपेक्षा की जाती है कि तदनुसार आपके द्वारा स्वजल परियोजना को आगे बढ़ाने में योगदान किया जायेगा।

भवदीय

(अनूप वधावन)
सचिव

संख्या : 568 / XII / 2008 / 86(16) / 2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाँऊ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य महा प्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. निदेशक, स्वजल परियोजना, देहरादून।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिषर, देहरादून।
10. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(स्म0सी0/उप्रेती)
अपर सचिव